EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By: - Aarav Anand

Date: 12 Dec 2025

Source:- जनसत्ता

व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेत, मोदी और ट्रंप ने फोन पर की बात

साथ काम करना जारी रखेंगे भारत-अमेरिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिवसीय व्यापार वार्ता के गुरुवार को समाप्त होने के साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।' हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के *पुतिन* के दौरे के बाद अब ट्रंप से सकारात्मक बातचीत, मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि नेताओं ने व्यापार, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर अमेरिका व्यापार समझौते से संबंधित भारतीय पेशकश से खुश है, तो उसे मुक्त व्यापार समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए।

भारत दौरे के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी में गति बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की, जिससे दोनों पक्षों के बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंचने के संकेत मिले। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत उस दिन हुई जब भारतीय और अमेरिकी वार्ताकारों ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दो दिवसीय वार्ता समाप्त की, उम्मीद है कि इससे भारत को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 फीसद के भारी शुल्क से राहत मिलेगी।

मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बातचीत को सौहार्दपूर्ण और सार्थक बताया। मोदी ने व्यापारिक संबंधों का कोई जिक्र किए बिना अपनी पोस्ट में कहा, 'हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय

बाकी पेज 8 पर

निर्माता कंपनी व साझेदार माइक्रोसाफ्ट पर गंभीर आरोप | तकनीक और हिंसा | चैटबाट ने भ्रम बढ़ाया व मां की हत्या के लिए उकसाया

हत्या में चैटजीपीटी की भूमिका को लेकर ओपनएआइ पर मुकदमा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

अमेरिका में हत्या-आत्महत्या के एक मामले में चैटजीपीटी की कथित भूमिका को लेकर निर्माता कंपनी ओपनएआइ मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित कनेक्टिकट की 83 वर्षीय महिला के परिवार ने चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआइ और उसके व्यापारिक साझेदार माइक्रोसाफ्ट पर मुकदमा कर आरोप लगाया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले चैटबाट ने उनके बेटे के 'भ्रम' को और बढ़ा दिया तथा अपनी मां की हत्या करने के लिए उकसाया।

यह अनोखा मामला है, जिसमें तकनीक पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इससे पहले पबजी जैसे गेमिंग एप पर आत्महत्या व हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था, कई मुल्कों ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी पुलिस ने बताया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी 56 वर्षीय स्टीन-एरिक सोएलबर्ग ने अगस्त की शुरुआत में कनेक्टिकट में स्थित घर में अपनी मां सुजैन एडम्स की पीट-पीटकर और गला घोंटकर हत्या कर दी। मां-बेटे इसी घर में रहते थे।

एडम्स के परिवार द्वारा गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को में स्थित अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ओपनएआइ ने 'एक दोषपूर्ण उत्पाद डिजाइन व वितरित किया जिसने एक उपयोगकर्ता के अपनी मां के बारे में मनगढ़ंत भ्रमों को सही साबित कर दिया।' अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) चैटबाट निर्माताओं के खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मुकदमे में कहा गया है, 'इन सभी बातचीत के दौरान, चैटजीपीटी ने एक ही खतरनाक संदेश को दोहराया कि स्टीन-एरिक को अपने जीवन में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, सिवाय चैटजीपीटी के।'

इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है, 'इसने (चैटजीपीटी) स्टीन-एरिक की भावनात्मक निर्भरता को बढ़ावा दिया, साथ ही उसके आसपास के लोगों को व्यवस्थित रूप से दुश्मन के रूप में चित्रित किया। चैटजीपीटी ने उसे बताया कि उसकी मां उस पर नजर रख रही है। चैटजीपीटी ने उसे बताया कि उससे जुड़े लोग, पुलिस अधिकारी और यहां तक कि दोस्त भी उसके खिलाफ काम करने वाले एजंट हैं।' ओपनएआइ ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया, 'यह एक बेहद दुखद स्थिति है, और हम मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे।'

बयान में कहा गया है, 'हम मानसिक या भावनात्मक परेशानी के संकेतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने तथा लोगों की वास्तविक सहायता के लिए चैटजीपीटी के प्रशिक्षण में लगातार सुधार कर रहे हैं। हम मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर संवेदनशील मौकों पर चैटजीपीटी की प्रतिक्रियाओं को भी मजबूत कर रहे हैं।'

चैटजीपीटी की शुरुआत वर्ष 2015 में ओपनएआइ ने एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में की थी, लेकिन वर्ष 2019 में ही कंपनी लाभ में आ गई। चैटजीपीटी आने के बाद अनेक दूसरी कंपनियों ने भी कृत्रिम मेधा आधारित चैटबाट शुरू की। कई शोध में एआइ को लेकर चिंताएं जताई जा चुकी हैं। एआइ के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए इसके नियमन की मांग भी तेज हो गई हैं।

दिल्ली में 11 की बजाय अब होंगे 13 जिले, शाहदरा खत्म

मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी, नागरिक सुविधाओं में तेजी की उम्मीद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या बढ़ गई है। पहले राष्ट्रीय राजधानी में 11 जिले थे जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं, जबकि एक पुराना जिला समाप्त कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि दिल्ली में अब 11 नहीं 13 राजस्व जिले होंगे। इसके अनुसार, शाहदरा जिला खत्म कर दिया गया है और तीन नए जिले पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली और बाहरी उत्तर बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई संरचना के तहत 11 जिलों को बढ़ाकर 13 और 33 सब-डिवीजन को बढ़ाकर 39 किया जाएगा। इससे अधिकारियों पर कार्यभार संतुलित होगा और नागरिकों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी। दिल्ली सरकार सभी नए जिलों में आधुनिक 'मिनी सचिवालय' स्थापित करेगी, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर राजस्व कार्यालय, एसडीएम, एडीएम, तहसील और उप-पंजीयक कार्यालय जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी और उनकी सीमाओं को सब-डिविजन के अनुरूप बनाया जाएगा।

पुनर्गठन के दौरान शाहदरा जिले को समाप्त कर इसका अधिकांश हिस्सा उत्तर पूर्वी जिले में शामिल किया गया है। उत्तर पूर्वी जिले में अब करावल नगर, गोकलपुरी, यमुना विहार और शाहदरा सब-डिवीजन होंगे। इसके साथ ही सीमापुरी और सीलमपुर सब-डिवीजन समाप्त कर दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली जिले में गांधी नगर के साथ विश्वास नगर और पटपड़गंज दो नए सब-डिवीजन बनाए गए हैं, जबकि प्रीत विहार और मयूर विहार सब-डिवीजन समाप्त किए गए।

तीन नए जिलों में पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तरी और बाहरी उत्तरी जिला शामिल हैं। इन जिलों में नए सब-डिवीजन बनाए गए हैं: पुरानी दिल्ली में सदर बाजार और चांदनी चौक; मध्य उत्तरी में शकूरबस्ती, शालीमार बाग और माडल टाउन; बाहरी उत्तरी में मुंडका, नरेला और बवाना। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्वी जिलों में सब-डिवीजन की संख्या 4-4, जबकि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में 2-2 रखी गई हैं। अन्य जिलों में प्रत्येक में 3-3 सब-डिवीजन होंगे।

शाहदरा को समाप्त कर इसका अधिकांश हिस्सा उत्तर पूर्वी जिले में शामिल किया गया है। तीन नए जिले पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली और बाहरी उत्तर बनाए गए हैं।

सभी नए जिलों में 'मिनी सचिवालय' स्थापित करेगी सरकार, एक ही स्थान पर राजस्व कार्यालय, एसडीएम, एडीएम, तहसील और उप-पंजीयक कार्यालय जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

जिला	नए/बचे सब-डिवीजन	
उत्तर पूर्वी	करावल नगर, गोकलपुरी, यमुना विहार, शाहदरा (पूर्व में जिला)	सीमापुरी और सीलमपुर समाप्त
पूर्वी दिल्ली	गांधी नगर, विश्वास नगर, पटपड़गंज	प्रीत विहार और मयूर विहार समाप्त
पुरानी दिल्ली	सदर बाजार, चांदनी चौक	नए जिले के रूप में शामिल
मध्य उत्तरी	शकूरबस्ती, शालीमार बाग, माडल टाउन	नए जिले के रूप में शामिल
बाहरी उत्तरी	मुंडका, नरेला, बवाना	नए जिले के रूप में शामिल

'वर्षों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया'

बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी। लंबे समय से दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं से मेल नहीं खाती थीं। अब शासन और अधिक सुचारू होगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया। इस फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

ये होंगे 13 जिले

मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पुरानी दिल्ली (नया जिला), मध्य उत्तर (नया जिला), बाहरी उत्तर (नया जिला)।

दबाव के दायरे में पिसता बचपन

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर प्रतिदिन करीब 38 है, जो पिछले बारह वर्षों में लगभग पैंसठ फीसद बढ़ी है। आखिर क्या वजह है कि कुछ बच्चों के भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है।

ज्योति सिडाना

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए अभिभावकों, समाज और सरकार की ओर से सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? हम ऐसा सुनते और पढ़ते आए हैं कि शिक्षा मनुष्य को शोषण, दमन, हिंसा और असमानता से लड़ना सिखाती है, उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। स्कूल बच्चों को समाज का सभ्य नागरिक बनना सिखाते हैं, उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि उनके भीतर जीवन शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है!

कुछ समय पहले दो बड़ी घटनाएं हुईं, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। राजस्थान में जयपुर के एक स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पीड़ित छात्रा को सहपाठियों द्वारा तंग करने और शिक्षकों की ओर से उसकी शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगे। दूसरी घटना में दिल्ली के एक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिक्षकों पर संबंधित छात्र को उपेक्षित-प्रताड़ित करने के आरोप लगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कभी शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले विद्यालय अब शिक्षा के बाजार बन गए हैं, जहां शिक्षा को ऐसे बेचा जाता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। आज के दौर में शिक्षा के व्यापार को सबसे अधिक फायदे वाला कारोबार माना जाता है। इस कारण अब हरेक नागरिक की शिक्षा तक समान पहुंच मुमकिन नहीं रह गई है।

देखा जाए तो बाजार ने शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, दोनों बदल डाले हैं। पहले विद्यार्थी तय करता था कि उसे किस तरह के विषय पढ़ने चाहिए, उसकी रुचि किसमें है। मगर अब बाजार तय करता है कि उसे कौन-सा विषय पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और कुशलता का निर्धारण भी बाजार ही करता है। यहां तक कि विद्यार्थी अपनी जिंदगी या करिअर में सफल है या असफल, यह भी बाजार ही तय करता है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अब संवेदनहीन, भावहीन और गैर-तार्किक मशीन में तब्दील हो चुका है, जिसका 'रिमोट' कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह विचार भी आ सकता है कि इससे तो पहले का समाज ही अच्छा था, जहां लोग निरक्षर या कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन स्वार्थ, लालच, धोखा, अविश्वास जैसे शब्दों से परिचित ही नहीं थे या उनसे दूर थे!

इतनी कम उम्र के बच्चे, जिन्हें सही से जीवन का अर्थ भी नहीं पता, संघर्षों और चुनौतियों ने जिन्हें अभी छुआ भी नहीं है, वे अचानक से जीवन को समाप्त करने जैसे निर्णय तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसकी क्या वजह

है? समस्या कहां है- परिवार में, शिक्षण संस्थानों में, नीति निर्माताओं में, प्रशासनिक व्यवस्था में, पाठ्यक्रमों में या फिर पूरा समाज ही अव्यवस्थित हो गया है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों में सही-गलत एवं नैतिक-अनैतिक के बीच निर्णय लेना सिखाना है, कल्याणकारी समाज की नींव को मजबूत करने की भावना पैदा करना है, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है, मगर धरातल पर ऐसा हो नहीं रहा है। रही सही कसर तकनीक के विकास ने पूरी कर दी है। इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया ने सूचना के प्रयास को भले ही आसान कर दिया है, लेकिन इससे बच्चों की कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता और कुछ अलग सोचने की क्षमता हाशिये पर आ गई है। समय और उम्र से पहले ही बच्चे वह सब देखने और जानने लगे हैं, जिसकी जानकारी होना उनके लिए अभी जरूरी नहीं है। साथ ही इस भौतिकतावादी समाज में अभिभावक भी अपने बच्चों को 'स्मार्ट' बनाने की जल्दी में जिंदगी की संवेदना और अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं।

> पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। केवल नीतियां बनाने से अगर काम चल सकता, तो ऐसी घटनाओं को कब का रोक लिया जाता। छोटी-सी उम्र में बच्चे अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो सोचिए कि उस समय उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और वे किस दर्द से गुजर रहे होंगे। यह सच है कि जब तक कोई पीड़ा असहनीय नहीं होती, इंसान हिम्मत नहीं हारता और अगर बच्चे हिम्मत हारने लगे हैं, तो सबको मिलकर इसके कारण और समाधान तलाशने होंगे।

अब परिवारों में बच्चों की संख्या भले ही एक या दो ही रहने लगी है, लेकिन अभिभावकों के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं है। इस कारण धीरे-धीरे बच्चे भी परिवार के स्थान पर स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। ऐसे में बच्चों से यह अपेक्षा करना कि वे संस्कृति और समाज के साथ समायोजन करेंगे, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे, बहुत दूर की कौड़ी है। बच्चों को एक उम्र तक डिजिटल दुनिया से दूर रखने के लिए कई देशों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, ताकि तकनीक के दुष्प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाया जा सके। दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चीन, इटली और हंगरी जैसे देशों में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और डिजिटल दुनिया की लत को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्राथमिक समाजीकरण जो पहले परिवार का दायित्व था, वह अब डिजिटल मीडिया करने लगा है। इसलिए अब इनके द्वारा उत्पन्न विचारों और सूचनाओं को हम बिना संदेह के विश्वसनीय और प्रामाणिक मानने लगे हैं। नतीजतन, बच्चे 'बंधक मस्तिष्क' और 'सीमित व्यक्तित्व' वाले बनते जा रहे हैं। मशहूर शिक्षाविद नील पोस्टमैन का कहना है कि आज की पीढ़ी निरर्थक विचारों से भरी और नकलची है, उसके पास जुमले हैं, मगर विचारधारात्मक चिंतन नहीं है। यह अलगाव का चरम स्तर है और ऐसे में समाज के विकास की दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल है। आज की पीढ़ी के बच्चों ने अपने बचपन को जिया ही नहीं, उनकी मासूमियत जल्दी परिपक्वता में बदल रही है, तकनीक एवं डिजिटल मीडिया ने उम्र एवं समय से पहले ही इनका बचपन छीन लिया है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में विद्यार्थी आत्महत्या की दर प्रतिदिन करीब 38 है, जो पिछले बारह वर्षों में लगभग पैंसठ फीसद बढ़ी है। वर्ष 2023 में मृतक विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों की संख्या 13,892 बताई गई है। ये तथ्य बहुत चौंकाने वाले हैं।

यह समस्या किसी एक की नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल नीतियां बनाने से अगर काम चल सकता, तो विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को कब का रोक लिया गया जाता। विचारणीय विषय यह है कि छोटी-सी उम्र में बच्चे अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, तो सोचिए कि उस समय उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और वे किस दर्द से गुजर रहे होंगे। कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, मगर दुनिया इस तरह बदलेगी, संभवतः ऐसी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी। यह सच है कि जब तक कोई पीड़ा असहनीय नहीं होती, तब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता और अगर हमारे बच्चे हिम्मत हारने लगे हैं, तो हम सबको मिलकर इसके कारण और समाधान तलाशने होंगे।

शिक्षा और संस्कृति

राजेंद्र जोशी

नई शिक्षा नीति, 2020 को स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में देखा जाता है। नीति दस्तावेज में 'भारतीयता' की भावना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण और स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़कर अधिगम की बात की गई है। शिक्षा के जमीनी ढांचे में विशेषकर राज्यों के स्तर पर इसका ठोस क्रियान्वयन अभी भी कई अड़चनों से घिरा हुआ है। दरअसल, नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम निर्धारण का केंद्र बनकर रह गई है, जबकि हमारी शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और लोक संस्कृति के संवर्धन को आगे बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। पांच साल बीत जाने के बाद अभी तक न तो एकरूपता का पाठ्यक्रम निर्धारित हो पाया है और न ही भाषाई स्तर पर कोई प्रगति दिखाई दे रही है। इसके बिना राज्यों के लिए इसको आगे समझना मुश्किल लग रहा है।

भारत के दर्शन में 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्' की अवधारणा शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों को विकसित करने का आधार प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति में भारतीय दर्शन और लोक परंपराओं को पाठ्यक्रम से जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन उसका अनुपालन अभी संस्थागत रूप से दृश्यमान नहीं हुआ है। अगर विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं और जन संस्कृति की समझ छोटे स्तर से ही दी जाए, तो भविष्य में भारतीय समाज एक जागरूक, सांस्कृतिक और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। संस्कृति का अर्थ केवल नृत्य, संगीत या चित्रकला नहीं है, बल्कि यह समाज के व्यवहार, भाषा, उत्सव, पहनावे और जीवन दृष्टि में प्रकट होती है। शिक्षा अगर केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन बन जाए, तो वह अधूरी है। नई नीति को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने के बीच संतुलन बनाना था।

देश के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, परंपराएं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आदि परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। उसकी जानकारी नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम और भारतीय दर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियमित रूप से होनी चाहिए। भारत में खूबसूरत हस्तशिल्प, हाथ से बनी कला और संस्कृति का संवर्धन आम लोगों के बीच है, लेकिन समाज और राज्यों में अलग-अलग रूप से सामाजिक कल्याण के लिए, सांस्कृतिक जागरूकता का अपना बड़ा महत्त्व रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख तो किया गया है, पर पांच साल के बाद भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया है। विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यापार या नौकरी पेशे में आ जाएगा, तब वह भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों से अछूता ही रहेगा। यहां का इतिहास, कला, भाषा और परंपरा की भावना ज्ञान के विकास द्वारा ही सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाता है।

हर राज्य में अपनी विशिष्ट कला-परंपराएं, लोकगीत, नृत्य रूप, हस्तशिल्प, चित्रकला और भाषाई शैलियां विद्यमान हैं, जो भारतीय पहचान को पोषित करती हैं। नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अवसर यह था कि इन क्षेत्रीय और लोककलाओं को शिक्षा के मुख्यधारा पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अपने समाज, संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और अपनापन विकसित हो। अफसोस की बात है कि यह विचार अभी तक दस्तावेजों में सीमित है। नीति में जिन पहलों का उल्लेख है, वे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ठोस विषय संरचना के रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं। नई नीति के अंतर्गत बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक, विद्यार्थियों के मातृभाषा में अध्ययन की सिफारिश की गई है। यह सैद्धांतिक रूप से भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

संस्कृति हमारी विरासत और भाषा की संरचना से तय होती है। कला-सांस्कृतिक पहचान जागरूकता को समर्थ करता है, समाज को उन्नत करने के अलावा सृजनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। भारतीय कलाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति के एक अध्याय में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति की बात की गई है। पर यह बात केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, तो हम भाषाओं के आधार पर कलाओं एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वे भारतीय भाषाएं भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं, उनके माध्यम से शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता शिक्षा नीति में होनी चाहिए।

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण और पश्चिमी शिक्षा माडल का प्रभाव गहराई तक पहुंच चुका है, तब भारतीय शिक्षा नीति को केवल प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वावलंबन के केंद्र के रूप में कार्य करना होगा। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को धरातल पर प्राप्त करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान और समाज- तीनों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। शिक्षा तभी सार्थक होगी, जब वह व्यक्ति को केवल रोजगार योग्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, रचनात्मक और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करे। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति एक नए भारत के निर्माण का दस्तावेज बन सकती है, अगर इसे औपचारिक नीतिगत सीमाओं से निकालकर सांस्कृतिक-सामाजिक क्रियान्वयन के स्तर तक ले जाया जाए। भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब उसकी शिक्षा भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़े मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगी।

दुनिया मेरे आगे

भारत में नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अवसर यह था कि क्षेत्रीय और लोककलाओं को शिक्षा की मुख्यधारा के पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अपने समाज, अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और अपनापन विकसित हो। अफसोस की बात है कि यह विचार अभी तक दस्तावेजों में सीमित है।

इंडिगो प्रभावित यात्रियों को देगी दस हजार रुपए मूल्य के यात्रा 'वाउचर'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

परिचालन संबंधी व्यवधानों से जूझ रही विमानन कंपनी इंडिगो उड़ानें रद्द होने या विलंब के कारण प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के यात्रा 'वाउचर' देगी। यह वाउचर तीन से पांच दिसंबर के दौरान उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को दिया जाएगा। यह नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मानदंडों के तहत उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगा। वहीं, इंडिगो ने बंगलुरु हवाई अड्डे से 60 उड़ानें रद्द कर दीं। ये उड़ान ऐसे समय में रद्द की गई हैं जब एअरलाइन ने विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए की निगरानी में आज 1,950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की अपनी योजना की घोषणा की है।

इंडिगो ने बंगलुरु हवाई अड्डे से 32 आगमन और 28 प्रस्थान सहित 60 उड़ानें रद्द कर दी हैं।

इंडिगो ने बयान में खेद जताते हुए कहा कि तीन, चार और पांच दिसंबर को यात्रा करने वाले उसके कुछ ग्राहक कई घंटों तक कुछ हवाई अड्डों पर फंसे रहे और उनमें से कई भीड़भाड़ से बुरी तरह प्रभावित हुए। इसमें कहा गया कि हम ऐसे गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपये मूल्य के यात्रा 'वाउचर' प्रदान करेंगे। इन यात्रा 'वाउचर' का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।' देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी को नियामकीय दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने परिचालन को स्थिर करने के लिए इसे शीतकालीन उड़ानों में 10 फीसद की कटौती करने का निर्देश दिया है।

इंडिगो दो दिसंबर को व्यवधान शुरू होने से पहले तक प्रतिदिन लगभग 2,300 उड़ानें संचालित कर रही थी। यह वाउचर मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत की गई प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है जिसके अनुसार इंडिगो उन ग्राहकों को उड़ान के 'अवरुद्ध' समय के आधार पर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रदान करेगी जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के

विमानन कंपनी ने बंगलुरु से 60 उड़ानें रद्द कीं

आज 1,950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना

भीतर रद्द कर दी गई थीं।

वहीं, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों ने इंडिगो मुख्यालय से विमानन कंपनी के संचालन, रकम वापसी और अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी शुरू कर दी। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को इंडिगो के गुरुग्राम मुख्यालय में एक निगरानी समिति के दो सदस्यों को तैनात करने का फैसला किया था ताकि रद्द उड़ानों की स्थिति, कर्मचारियों की तैनाती, अनियोजित अवकाश एवं कर्मचारियों की कमी से प्रभावित मार्गों की निगरानी की जा सके।

डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर तीन बजे अपने कार्यालय में तलब किया और हाल में परिचालन व्यवधानों से संबंधित व्यापक एवं अद्यतन जानकारी की एक पूरी रपट मांगी। विमानन नियामक के बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, डीजीसीए कार्यालय के दो अधिकारियों, एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक को इंडिगो के कारपोरेट कार्यालय में तैनात किया जाएगा ताकि घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने की स्थिति, धन वापसी की स्थिति, समय पर प्रदर्शन, नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार यात्रियों को मुआवजा एवं सामान वापसी की निगरानी की जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल आज करेगा विचार

ओमान के निचले सदन ने भारत के साथ एफटीए को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

ओमान के निचले सदन 'शूरा परिषद' ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी है। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को इस समझौते पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इस पर बातचीत नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी जो इस वर्ष संपन्न हो गई।

इस प्रकार के समझौते में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी हद तक कम या समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में ओमान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत का पहले से ही जीसीसी के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ इसी तरह का समझौता है जो मई 2022 में लागू हुआ था।

वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया था कि प्रासंगिक प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए 'कैबिनेट नोट' का मसौदा संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है। दोनों पक्ष अब आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। भारत में मुक्त व्यापार समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जाती है। 'शूरा परिषद' या मजलिस शूरा ने सीईपीए के मसौदे पर अपनी चर्चा बुधवार को पूरी कर ली। चर्चा के समापन पर परिषद ने समझौते को मंजूरी दे दी। परामर्श परिषद ओमान का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को यहां होने वाली अपनी बैठक में इस समझौते पर विचार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने जार्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डालर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डालर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डालर) था। भारत के प्रमुख आयात पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया हैं जिनकी कुल आयात में हिस्सेदारी 70 फीसद से अधिक है। अन्य प्रमुख उत्पादों में प्रोपलीन और एथिलीन पालिमर, पेट कोक, जिप्सम, रसायन, लोहा और इस्पात तथा अपरिष्कृत एल्युमीनियम शामिल हैं।

'यूरोपीय संघ के साथ एफटीए को अंतिम रूप देने में आ रही बाधाएं दूर कर लेंगे'

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का गुरुवार को भरोसा जताया।

गोयल ने समझौते पर हस्ताक्षर होने की कोई संभावित समयसीमा न बताते हुए कहा कि इटली जैसे देश भारत को अपनी शराब एवं मोटर वाहन निर्यात कर सकेंगे और इसके बदले में भारत 27 देशों के इस समूह को व्हिस्की, वस्त्र एवं मोटर वाहन कलपुर्जे निर्यात कर सकेगा। गोयल ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई अपनी चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि हमें भरोसा है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें अब भी सहमति बनानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के

वार्ताकार दल एक अच्छा समझौता कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

गोयल ने इटली-भारत व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-यूरोपीय संघ एफटीए एक निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं संतुलित दस्तावेज होगा जो सभी देशों के लिए लाभकारी होगा। इस अवसर पर इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भी उपस्थित रहे। गोयल और ताजानी दोनों ने वैश्विक बाजार में कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति के लिए लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग की जरूरत पर बल दिया।

'एजेंटिक' एआइ के लिए माइक्रोसाफ्ट व चार बड़ी कंपनियों में करार | कदम | भारत में निवेश करने को लेकर बहुत उत्साहित : नडेला

'एज्यूर को विश्व के कंप्यूटर के रूप में विकसित कर रहे हैं'

बंगलुरु, 11 दिसंबर (भाषा)।

'माइक्रोसाफ्ट' के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि हम भारत में निवेश करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं ताकि हम यहां सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का बुनियादी ढांचा ला सकें। यह 17.5 अरब अमेरिकी डालर का निवेश है। नडेला ने इसे एशिया में माइक्रोसाफ्ट का सबसे बड़ा निवेश बताया। देश भर में कंपनी के 'क्लाउड नेटवर्क' के तेजी से विस्तार पर जोर दिया।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने गुरुवार को कहा कि कंपनी भारत के कृत्रिम मेधा (एआइ) परिवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 'एज्यूर' को विश्व के कंप्यूटर के रूप में विकसित कर रहे हैं और हमारे पास दुनिया भर में 70 से अधिक डेटा सेंटर क्षेत्र हैं। भारत में हमारी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि माइक्रोसाफ्ट, 'क्लाउड' क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के साथ एआइ-संचालित भविष्य के लिए लाखों भारतीयों को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। माइक्रोसाफ्ट ने चार प्रमुख आइटी कंपनियों कान्गिजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के साथ रणनीतिक साझेदारी की भी घोषणा की। ये कंपनियां 'एजेंटिक' एआइ को अपनाने में तेजी लाने के लिए माइक्रोसाफ्ट के साथ मिलकर काम करेंगी। 'माइक्रोसाफ्ट' के यहां आयोजित एक कार्यक्रम में नडेला ने कहा कि हम भारत में निवेश करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं ताकि हम यहां सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का बुनियादी ढांचा ला सकें। यह 17.5 अरब अमेरिकी डालर का निवेश है। नडेला ने इसे एशिया में माइक्रोसाफ्ट का सबसे बड़ा निवेश बताया। माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन ने देश भर में कंपनी के 'क्लाउड नेटवर्क' के तेजी से विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में नेटवर्क है और हमने जियो के साथ भी साझेदारी की है।

'एज्यूर' माइक्रोसाफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक व्यापक 'क्लाउड कंप्यूटिंग' मंच है। इस पर कंपनियां एवं डेवलपर अपनी एप्लिकेशन, वेबसाइट, डेटाबेस, स्टोरेज, एआइ मॉडल तथा सर्वर आनलाइन बना, चला तथा प्रबंधित कर सकते हैं.. वह भी बिना अपने 'फिजिकल सर्वर' खरीदे। उन्होंने कहा कि एक नया डेटा सेंटर क्षेत्र 2026 में चालू हो जाएगा। नडेला ने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि 2026 में देश के दक्षिण क्षेत्र में हमारा एक नया डिजिटल सेंटर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है।

उन्होंने एआइ के बढ़ते उपयोग के इस युग में डिजिटल संप्रभुता एवं साइबर सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। नडेला कहा कि हम संप्रभुता को लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि संप्रभुता के लिए विकल्पों का एक व्यापक खंड मौजूद हो। इसलिए आपके पास पब्लिक 'क्लाउड' है, पब्लिक क्लाउड में संप्रभु नियंत्रण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि संप्रभुता को सुरक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

भारत ने सुरक्षा परिषद में कहा

तालिबान के साथ व्यवहारिक संबंध कायम करने का पक्षधर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि वह तालिबान के साथ व्यावहारिक संबंध कायम करने का पक्षधर है, क्योंकि केवल दंडात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित करने से पुराने दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने कहा, 'भारत संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करता है कि वह ऐसे नीतिगत कदम उठाए, जिनसे अफगानिस्तान के लोगों को स्थायी लाभ पाने में मदद मिले।' उन्होंने कहा, 'भारत तालिबान के साथ व्यावहारिक संबंध कायम करने का पक्षधर है। संबंधों को लेकर एक स्पष्ट नीति से सकारात्मक कदमों को बढ़ावा मिलना चाहिए। केवल दंडात्मक कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करने से पुराना दृष्टिकोण जारी रहेगा। पिछले साढ़े चार साल से हम ऐसा दृष्टिकोण देखते आ रहे हैं।' उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

हरीश ने कहा कि काबुल में दिल्ली के तकनीकी मिशन का दूतावास का दर्जा बहाल करने का भारत सरकार का हालिया निर्णय इस संकल्प को मजबूती से दर्शाता है।' उन्होंने कहा कि हम सभी संबंधित पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे ताकि अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और दक्षता विकास पहल में अपना योगदान बढ़ा सकें, जो अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।' अक्तूबर में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी छह दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली आए थे। वह 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वरिष्ठ तालिबानी मंत्री थे।

हरीश ने कहा, 'भारत संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करता है कि वह ऐसे नीतिगत कदम उठाए, जिनसे अफगानिस्तान के लोगों को स्थायी लाभ पाने में मदद मिले।'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें दिल्ली के तकनीकी मिशन को काबुल में दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की गई और अफगानिस्तान में विकास कार्यों को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया गया। भारत ने अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने दूतावास से अधिकारियों को वापस बुला लिया था। जून 2022 में, भारत ने काबुल में एक तकनीकी टीम को तैनात कर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति फिर से स्थापित की।

हरिश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रखता है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों जैसे आइएसआइएल, अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद समेत उनके सहयोगियों तथा लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को समन्वित करना चाहिए, ताकि वे सीमा पार आतंकवाद में लिप्त न हों।

अमेरिका की सांसद सिंडी कमलागर-डोव ने कहा

ट्रंप ने रुख नहीं बदला तो वे भारत को खो देने वाले राष्ट्रपति बन जाएंगे

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 11 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका की एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति नीतियां रणनीतिक भरोसे और पारस्परिक समझ को वास्तविक व स्थायी नुकसान पहुंचा रही हैं। द्विपक्षीय संबंधों को हुए नुकसान को कम करने के लिए वाशिंगटन को अविश्वसनीय तत्परता के साथ कदम उठाने होंगे।

कैलिफार्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद सिंडी कमलागर-डोव ने कहा, '...अगर ट्रंप अपनी नीति में बदलाव नहीं करते, तो वह भारत को खो देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। और ज्यादा साफतौर पर कहा जाए तो जिन्होंने भारत को दूर कर दिया जबकि रूसी साम्राज्य को सशक्त किया। उन्होंने ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को तोड़ा है और लातिन अमेरिका को खतरे में डाला है। यह वह विरासत नहीं है जिसपर किसी राष्ट्रपति को गर्व होना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी और बताया जाएगा कि भारत के प्रति ट्रंप की शत्रुता कहां से शुरू हुई, तो वे किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करेंगी जिसका हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से कोई लेना-देना नहीं है। यह चीज है उनका नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर व्यक्तिगत जुनून। यह भले ही हास्यास्पद हो, लेकिन इसका जो नुकसान होगा, उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।'

ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त किया, जिसमें मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष भी शामिल है। कमलागर-डोव संसद की दक्षिण और मध्य एशिया विदेश मामलों की उप समिति की बैठक में 'यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: सिक्योरिंग अफ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' विषय पर संबोधन दे रही थीं। कमलागर-डोव ने भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों की आलोचना की।

इन नीतियों में भारत पर दुनिया में सबसे अधिक 50 फीसद शुल्क लगाना, एच1बी वीजा पर 100,000 अमेरिकी डालर का शुल्क लगाना शामिल है। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में रहने और काम करने के लिए एच1बी वीजा का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों से वास्तविक व स्थायी नुकसान हो रहा है और देश को अविश्वसनीय तत्परता के साथ इस नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

अमेरिका की सांसद ने कहा कि जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी और बताया जाएगा कि भारत के प्रति ट्रंप की शत्रुता कहां से शुरू हुई, तो वे किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करेंगी जिसका हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से कोई लेना-देना नहीं है। यह चीज है उनका नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर व्यक्तिगत जुनून।

अर्थव्यवस्था संभालने में ट्रंप की लोकप्रियता में आई कमी

वाशिंगटन, 11 दिसंबर (एपी)।

अर्थव्यवस्था और आव्रजन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में इस साल काफी गिरावट आई है। 'एपी-एनओआरसी' के एक नये सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है।

एपी-एनआरओसी सर्वेक्षण से खुलासा।

यह इस बात का ताजा संकेत है कि जिन दो अहम मुद्दों के आधार पर ट्रंप लगभग एक साल पहले चुनाव जीते थे, वो अब उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। उनकी पार्टी 2026 के मध्यावधि चुनावों की तैयारी शुरू कर रही है। द एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फार पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेक्षण में पाया गया है कि अब सिर्फ 31 फीसद अमेरिकी वयस्क ही ट्रंप के अर्थव्यवस्था संभालने के तरीके से सहमत हैं।

मार्च में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था और अब इसमें कमी आ गई है। यह ट्रंप के पहले या दूसरे कार्यकाल में एपी-एनओआरसी सर्वेक्षण में दर्ज की गई सबसे कम आर्थिक स्वीकृति रेटिंग है।

भारत में विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेशी दूसरे स्थान पर

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।

देश में नागरिकता पहचान पंजीकरण (एसआइआर) को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच अक्सर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बयानबाजी तेज हो जाती है। संसद में पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में वैध पर्यटन वीजा लेकर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सूची में बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है।

साल 2024 में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। इनकी संख्या 1804586 रही, जो कुल पर्यटक का 18.13 फीसद हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2024 में कुल 99.52 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। साल 2020 में इनकी संख्या 27.45 लाख रही थी। कोरोना महामारी के बाद भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले पांच सालों में चार गुना से ज्यादा बढ़ गई है। वर्ष 2024 इस अवधि का सबसे सक्रिय वर्ष रहा।

> *साल* 2024 में कुल 9951722 विदेशी नागरिक वीजा लेकर भारत आए। इनमें बांग्लादेशी नागरिक की संख्या 1750165 रही जो कुल विदेशी पर्यटक का 17.58 फीसद है। यानी भारत आने वाला करीब हर पांचवा नागरिक बांग्लादेश से है।

वर्ष 2024 में भारत आने वाले विदेशी नागरिकों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा। यहां से 1804586 आगमन हुआ। बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा। यहां से 17,50,165 आगमन हुआ और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा। यहां से 10,28,557 आगमन हुआ।

पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले पर्यटक लगातार भारत आने में रुचि दिखा रहे हैं। वर्ष 2020 में जहां यह संख्या लगभग 5.49 लाख थी, वहीं 2024 तक यह संख्या बढ़कर 17.50 लाख तक पहुंच गई।

मंत्री ने बताया कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थाटन कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद), पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए देखो अपना देश, अंतरराष्ट्रीय सुरभि तथा भारत वर्ष प्रदर्शन जैसे अभियान शामिल हैं।

टी20 विश्व कप 2026 के टिकट की कीमत 100 रुपए

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा)।

टी20 विश्व कप 2026 के टिकटों की बिक्री गुरुवार से शुरू हो गई है जिसमें कुछ जगहों के लिए पहले चरण में कीमत 100 रुपए या 1000 श्रीलंकाई रुपए जितनी कम रखी गई है। भारत और श्रीलंका सात फरवरी से आठ मार्च तक मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने अपने प्लेटफार्म पर टी20 विश्व कप के 10वें चरण के टिकटों की बिक्री की घोषणा की जिसमें 20 टीम का टूर्नामेंट आठ जगहों पर खेला जाएगा। भारत में विश्व कप के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेजबान शहर होंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो (दो जगह) और कैंडी दो स्थान होंगे। गत चैंपियन भारत टूर्नामेंट के पहले दिन तीन मैचों में से एक में अमेरिका से भिड़ेगा।

क्रिकेट

> *भारत* में विश्व कप के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेजबान शहर होंगे।

आइसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, टिकट बिक्री का पहला चरण अब तक के सबसे सुलभ और वैश्विक आईसीसी टूर्नामेंट को आयोजित करने की हमारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। टी20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा नजरिया स्पष्ट है कि हर प्रशंसक को विश्व स्तरीय क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति कुछ भी हो।

Source:- दैनिक जागरण

केसरिया स्तूप अमूल्य धरोहर, सुविधाओं का होगा विस्तार

- मुख्यमंत्री ने केसरिया में निर्माणाधीन टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का किया अवलोकन
- कहा-ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता

संवाद सहयोगी, जागरण • केसरिया (पूर्वी चंपारण) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केसरिया बौद्ध स्तूप राज्य ही नहीं देश की अमूल्य धरोहर है। इसके संरक्षण के साथ ही यहां पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देना सरकार की प्राथमिकता है। स्तूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर को संचालित कर पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके निर्माण से पर्यटकों को सहूलियत होगी और बौद्ध धर्म के विभिन्न आयाम तथा बिहार के गौरवशाली गाथा को वे जान सकेंगे। वे गुरुवार को केसरिया दौरे के क्रम में बोल रहे थे। सरकार गठन के बाद जिले में उनका यह पहला दौरा था।

सीएम ने सबसे पहले स्तूप के समीप कैफेटेरिया परिसर में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से 17.15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सीएम को सेंटर की उपयोगिता एवं निर्माण प्रगति की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्तूप परिसर में जाकर वहां की व्यवस्था की जानकारी ली। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव ताजपुर पटखौलिया गांव था, जहां उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा राजकीय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक

पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया स्तूप गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां विकसित की जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साथ में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व अन्य • सौ. आइपीआरडी

विद्यालय का अवलोकन किया। अस्पताल के अवलोकन के क्रम में सीएम ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने स्कूल के समीप लगाए गए विभिन्न स्टालों को भी देखा, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं जीविका दीदियों के अलावा अन्य सरकारी कर्मी उपस्थित थे। मानदेय वृद्धि से उत्साहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रति आभार प्रकट किया। सीएम ने महिलाओं को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

संवाद में छात्राओं से अच्छे से पढ़ाई की नसीहत : मुख्यमंत्री राजकीय मध्य विद्यालय केसरिया बालक परिसर स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए सीएम ने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। छात्राओं से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करें। सरकार आपको ठीक से पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए ख्याल रख रही है। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी थे।

71 प्रतिशत बिहार से बाहर करते हैं प्रवासन

जागरण संवाददाता, पटना: अनुग्रह नारायण सिंह इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज में बिहार से मौसमी प्रवासन के विषय पर गुरुवार से राष्ट्रीयस्तर के दो दिवसीय परामर्श की कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयोजन में बिहार के साथ गुजरात, केरल, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली के की अकादमिक जगत के शोधार्थी, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि, बिहार के विभिन्न जिलों में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक पुष्पेंद्र कुमार ने जातिगत आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बिहार से 63 लाख से ज्यादा श्रमिक प्रवासन करते हैं। इसमें केवल 25 प्रतिशत ही राज्य के अंदर प्रवासन करते हैं। 71 प्रतिशत अन्य राज्यों में और तीन प्रतिशत से ज्यादा देश के बाहर जाते हैं। बिहार के पलायन पर काम करने वाले प्रो. राम बाबू भगत और अविरल शर्मा ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। सत्र का संचालन साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के डा. रवि ने किया।

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों की प्रस्तुति : इसके बाद प्रवासी श्रमिकों के अधिकाओं की रक्षा के लिए सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों की प्रस्तुति हुई। श्रम संसाधन विभाग के सहायक श्रम आयुक्त डा. गणेश झा ने बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण दिया। एक्शन ऐड संस्था के शत्रुघ्न दास ने गयाजी जिले में ईंट-भट्टा मजदूरों की परिस्थिति और उनकी संस्था द्वारा बंधुआ मजदूर छुड़ाने के प्रकरण की जानकारी दी।

बाल श्रम और मानव तस्करी पर हुई बातें

तीसरे सत्र में बाल श्रम और मानव तस्करी के ऊपर काम करने वाली संस्थाओं ने अपने कार्यों की प्रस्तुति दी। इस सत्र में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डा. तुलसीराम मांझी और राकेश कुमार ने आयोग के काम को प्रस्तुत किया। न्याय नेटवर्क की एडवोकेट संजू सिंह और अदिति संस्था ने अपनी संस्थाओं के काम की जानकारी दी। सत्र का संचालन सेंटर डायरेक्ट संस्था के प्रमोद शर्मा ने किया। अंतिम सत्र का संचालन प्रोफेसर हिमांशु कुमार ने किया।

प्रदूषण की मार, प्रदेश में सात प्रतिशत दमा और पांच प्रतिशत सांस रोगी

जागरण संवाददाता, पटना : पटना में बढ़ते धूल-प्रदूषण का सीधा असर लोगों के फेफड़ों पर पड़ रहा है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी बिहार चैप्टर और आइजीआइएमएस, एम्स सहित विभिन्न अस्पतालों के ओपीडी आंकड़ों के अनुसार, जिले की आबादी में सात प्रतिशत लोग दमा (अस्थमा) और पांच प्रतिशत लोग अन्य सांस संबंधी रोगों से जूझ रहे हैं। यह जानकारी इंडियन चेस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष और नैपकान 2025 आयोजन सचिव प्रो. डा. सुधीर कुमार ने गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस के उद्घाटन समारोह में दी। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खां ने किया।

इंडियन चेस्ट सोसाइटी के 27वें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कांफ्रेंस का उद्घाटन करते राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एवं चिकित्सक। • जागरण

- धूल-प्रदूषण से घट रही पटना वालों के फेफड़ों की क्षमता
- राज्यपाल ने किया नैपकान का शुभारंभ, एक साथ कई जगह हुए कार्यक्रम

उत्तर बिहार से भी बड़ी संख्या में आते हैं मरीज : डाक्टरों के अनुसार पटना के अस्पतालों में उत्तर बिहार खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली और आसपास के जिलों से काफी मरीज पहुंचते हैं। मौसम में बदलाव अस्थमा को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। पहले फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में मामले बढ़ते थे, लेकिन अब प्रदूषण के कारण पूरे साल मरीजों की संख्या अधिक हो रही है।

दुनिया के हर 10 में एक अस्थमा मरीज भारत में : अमेरिका से आए डा. अतुल सी मेहता ने बताया कि अस्थमा बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर गैर-संचारी बीमारी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में 262 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में छह प्रतिशत बच्चे और दो प्रतिशत व्यस्क अस्थमा से ग्रसित हैं। वैश्विक स्तर पर हर 10 में कम से कम एक मरीज भारत का है।

पटना में प्रदूषण 50 गुना तक अधिक : आयोजन समिति के अध्यक्ष डा. सुधीर कुमार ने बताया कि पटना का एक्यूआइ सामान्य स्तर 50 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन कई बार 200–300 के पार पहुंच जाता है। यही कारण है कि जिले में दमा और सांस रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के दुरुपयोग और बच्चों में फास्ट फूड की बढ़ती प्रवृत्ति भी अस्थमा को बढ़ावा दे रही है। छह महीने से एक साल के बच्चों में अनावश्यक एंटीबायोटिक इस्तेमाल से भविष्य में अस्थमा की आशंका बढ़ जाती है।

हर साल 20 हजार सांस रोगी आते हैं पटना : कार्यान्वयन समिति के अतिरिक्त सचिव डा. मनोहर कुमार ने बताया कि कोविड के बाद फेफड़ों की क्षमता पर प्रदूषण का असर और बढ़ा है। पूरे बिहार से हर साल करीब 20 हजार मरीज सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए पटना पहुंचते हैं। पटना की हवा में पीएम 2.5 की मात्रा मानक से तीन गुना अधिक पाई जाती है, जिसका ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होता है।

बचपन से देखभाल पर जोर : इंग्लैंड के डा. एम मुनव्वर ने कहा कि यदि बच्चे के जन्म के बाद पहले छह महीनों में उसकी सही देखभाल की जाए और मां व बच्चे में विटामिन डी का स्तर सही हो, तो आगे चलकर अस्थमा होने की संभावना काफी कम रहती है।

एम्स में अत्याधुनिक जांच पर कार्यशाला : नैपकान के तहत पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (पीएफटी) तथा मेडिकल थोरैकोस्कोपी विषय पर दो विशेष कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया गया। इसमें डा. एसके छिब्बरा ने स्पाइरोमेट्री तकनीक पर व्याख्यान एवं तकनीक को कुशलता से बताया।

बीमारी के लक्षण

- सांस फूलना
- लगातार या तेज खांसी
- बलगम निकलना
- थकान और वजन कम होना
- तेज खांसी की स्थिति में बेहोशी
- सांस छोड़ने में अधिक परेशानी

ऐसे करें बचाव

- धूल, धुएं और प्रदूषण वाले माहौल से बचें
- रसोईघर में निकासी की उचित व्यवस्था रखें
- डाक्टर की सलाह से हर साल फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाएं
- धूम्रपान करने वालों से दूरी बनाएं

उपचार के प्रमुख उपाय

- डाक्टर की सलाह के अनुसार इन्हेलर का उपयोग
- हर साल फ्लू वैक्सीन
- 50 उम्र या डायबिटीज रोगियों को निमोनिया वैक्सीन

12 प्रयोगशालाओं में ट्रेनिंग, जूनियर डाक्टरों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी

एनएमसीएच के चेस्ट विभागाध्यक्ष डा. अजय कुमार ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम आइजीआइएमएस, एम्स पटना और मेदांता समेत 12 लैब में आयोजित किया जा रहा है। यहां बाहरी विशेषज्ञ जूनियर डाक्टरों को फेफड़ों की अल्ट्रासाउंड, एआइ-आधारित एमआरआइ/सीटी तकनीक, आइसीयू वेंटिलेशन, टीबी व सांस रोगों के उन्नत इलाज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले दिन सैकड़ों डाक्टर्स ने भाग लिया।

अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक बस निर्माण की इकाई के लिए दिया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : अशोक लेलैंड ने बिहार में इलेक्ट्रिक बस निर्माण के लिए उत्पादन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को उद्योग वार्ता कार्यक्रम में इस आशय का प्रस्ताव आया। वहीं, 32 निवेशकों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। 'उद्योग वार्ता' इस मायने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसमें बिहारी निवेशकों की संख्या अधिक थी।

गुरुवार को उद्योग वार्ता कार्यक्रम में शामिल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। • सौ : विभाग।

यशपाल साचर (वाइस प्रेसिडेंट, अशोक लेलैंड) ने इलेक्ट्रिक बस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बिहार में परिचालित 'पिंक बस' को देखते हुए महिलाओं के लिए ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की जा सकती है। विपिन कुमार झा (निदेशक, रोबोटिक्स प्रोग्राम और कोलोरेक्टल सर्जरी, सवेरा कैंसर एंड मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल) ने रोबोटिक्स सर्जरी की अहमियत को रेखांकित करते हुए इसमें निवेश करने और सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। सिद्धार्थ लखानी (निदेशक, कोका कोला एसएलएमजी) ने बिहार सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और अपने प्रस्तावित उद्योग की रूपरेखा पर चर्चा की। निवेशकों ने सरकार से आयात-निर्यात प्रक्रियाओं में भी सहयोग की मांग की।

इन क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों पर चर्चा

- दुग्ध उत्पादन एवं संबंधित उत्पाद उद्योग
- बिहार फिल्म सिटी की स्थापना में निवेश
- बिजली संबंधित उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- फर्नीचर, एजुकेशनल इंस्टीच्यूट, और हास्पिटल सेक्टर
- लेदर के सामान का निर्माण एवं निर्यात
- गन्ना उद्योग का विस्तार

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी निवेशकों को आश्वासन दिया कि 'उद्योग वार्ता' राज्य सरकार को अच्छे और गंभीर निवेशकों के साथ सीधे काम करने का अवसर प्रदान करेगी और सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की नई नीति लानी पड़ेगी या पुरानी नीतियों में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार बिना किसी विलंब के वह करेगी। जिन निवेशकों को ज़मीन की आवश्यकता थी या अन्य दिक्कतें आ रही थीं, उनके मामलों को मुख्य सचिव ने गंभीरता से सुना और तत्काल संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निदेश दिए। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव, कुंदन कुमार, निदेशक, मुकुल कुमार गुप्ता, ऊर्जा विभाग के सचिव, मनोज कुमार सिंह, और गन्ना कमिश्नर, अनिल कुमार झा भी उपस्थित रहे।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिले दो पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावरलाइन ट्रांसटेक इंडिया अवाड्र्स-2025 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एक दिन पहले नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने कहा कि यह पुरस्कार हमारी टीम की कड़ी मेहनत, समर्पण और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। बीएसपीटीसीएल को पिछले तीन वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक 2,018 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन में वृद्धि (220 केवी और उससे अधिक) तथा सर्वाधिक 5,260 ट्रांसफार्मेशन कैपेसिटी में वृद्धि (220 केवी और उससे अधिक) के लिए

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पावरलाइन ट्रांसटेक इंडिया अवाड्र्स-2025 के दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया

पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने संचरण लाइनों और ट्रांसफार्मर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करके बिहार की बिजली ट्रांसमिशन क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। पावरलाइन ट्रांसटेक इंडिया अवाड्र्स का उद्देश्य भारतीय बिजली के संचरण क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देना है। विजेता का चय सीईए, पीएफसी और राज्य उपयोगिताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा के आधार पर किया गया है। ट्रांसटेक इंडिया विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित एक प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसमें इस वर्ष 2,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सरकार ने तीन नए विभागों के बीच काम का किया बंटवारा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : राज्य सरकार ने हाल ही में गठित किए गए तीन विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया है। सत्ता में वापसी के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने तीन विभागों के गठन का निर्णय लिया था। नौ दिसंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों के गठन की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय ने अब विभागों के बीच कार्यों के बंटवारे के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जिन तीन विभागों का गठन किया गया है उनमें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, सिविल विमानन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। सरकार का सर्वाधिक फोकस राज्य में रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने पर है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में बेहतर

विभाग और उनके कार्य एक नजर में

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- रोजगार से संबंधित अधिनियम/नियमावली का सृजन
- रोजगार के लिए निबंधन एवं रोजगार निदेशालय का गठन
- रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नीतियों का निर्माण
- रोजगार मेला का आयोजन, रोजगार से संबंधित ई-पोर्टल का निर्माण-संचालन
- निजी कंपनियों, उद्योगों व प्रतिष्ठानों एवं एमएसएमई इकाइयों के साथ रोजगार के लिए संपर्क
- विशेष नियोजन निदेशालय
- युवाओं के लिए प्रक्षेत्रवार व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ)
- केंद्र सरकार के कौशल विकास के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से समन्वय
- अप्रेन्टिस शिप योजनाएं लागू करना एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण
- विभिन्न विभागों, जैसे श्रम संसाधन, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग से रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का समन्वय।
- चलायी जा रही योजनाओं के साथ समन्वय
- बिहार कौशल विकास मिशन से संबंधित कार्य
- राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेहरू युवा केंद्र, बिहार युवा आयोग से संबंधित कार्य
- विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
- युवा प्रतिभा की पहचान एव पोषण, युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य

सिविल विमानन विभाग के कार्य

- सरकारी वायुयान, हेलीकाप्टर इत्यादि की खरीददारी, संधारण तथा उनकी उड़ान से संबंधित कार्य
- राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियमन और संगठन
- राज्य सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट एवं सभी हेलीपोर्ट का विकास, संचालन एवं नियंत्रण
- भारत सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट के संबंध में समन्वय
- बिहार उड्डयन संस्थान, वैमानिकी प्रशिक्षण तथा उसका विनियमन
- विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
- विभाग में गठित सभी बोर्ड, निगम एसं संस्थाओं से संबंधित कार्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण

25 जगहों पर बनेंगे वेंडिंग जोन, जलापूर्ति जलनिकासी की होगी जीआइएस मैपिंग

मंत्री नितिन नवीन ने नगर निगम के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

बढ़ेंगी सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : राजधानी पटना में 25 जगहों पर नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इससे संबंधित दिशा-निर्देश दिए। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 25 जगहों को चिह्नित करने का टास्क सौंपा गया है। इसके साथ ही मंत्री ने जल निकासी, जलापूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क की जीआइएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैपिंग करने का निर्देश दिया है। कचरा प्रबंधन एवं संग्रहण के लिए नई गाड़ियों की खरीद का निर्देश भी दिया गया है।

समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा, बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर सहित निगम के सभी वरीय अधिकारी शामिल हुए

नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक करते मंत्री नितिन नवीन ● सौ. विभाग

और विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की प्रस्तुति दी। मंत्री ने सबसे पहले सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था तथा स्वच्छता से जुड़े सूचकों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सफाई व्यवस्था को और अधिक वैज्ञानिक एवं समयबद्ध बनाया जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी वार्ड में पेयजल आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए।

मंत्री नितिन नवीन ने राम चक बैरिया स्थित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी चरण कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रणाली और कचरे के पृथक्करण पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि प्रोसेसिंग यूनिट पर भार कम हो और दक्षता बढ़े।

फील्ड विजिट करें अधिकारी, काम का करें मूल्यांकन : मंत्री ने पटना नगर निगम की टीम को समय-समय पर फील्ड निरीक्षण करने और कार्यों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। स्वच्छता में पटना को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थान प्राप्त होने पर मंत्री ने शहरवासियों, नगर निगम के सभी अधिकारियों, कर्मियों और सफ़ाई योद्धाओं को हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि टीम वर्क, समर्पण और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा।

बंगाल में चिंतित करने वाला घटनाक्रम

अवधेश कुमार

बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और उनके जख्मों को कुरेदना है

मुर्शिदाबाद में समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर ● एएनआइ

इस तस्वीर की हमने शायद ही कल्पना की हो कि देश में कहीं पर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव डाली जाएगी और उसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा इलाके में प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रख दी। हुमायूं कबीर पश्चिम मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं। वे लंबे समय से सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे थे कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करेंगे। इस कारण बंगाल के अंदर और देश में असहजता का माहौल कायम हो रहा था। अलग-अलग मंचों से इसे रोकने की मांग भी की गई, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। केवल हुमायूं कबीर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कोई भी राज्य सांप्रदायिकता भड़काने और तनाव फैलाने की योजना वाले हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता, हिरासत में लेता या कम से कम उसे नजरबंद करता। इसके साथ ऐसे कार्यक्रम पर रोक भी लगाता। मुर्शिदाबाद का दृश्य इसके विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस उस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। जब पुलिस-प्रशासन को राजनीतिक नेतृत्व से रोकने का कोई आदेश नहीं था तो वह ऐसी ही भूमिका निभाएगा। किसी को भी कानूनी रूप से वैध जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना करोड़ों हिंदुओं-सिखों की भावनाओं को चोट पहुंचाना और उनके जख्मों को कुरेदना है। यह हर दृष्टि से अस्वीकार्य है। 1529 में बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद निर्माण के विरुद्ध वर्षों का संघर्ष अब सबको पता है। अंततः स्वतंत्रता के बाद आंदोलन और फिर आगे न्यायिक संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर निर्माण किया गया। बावजूद इसके देश का एक वर्ग मानता है कि बाबर के साथ उसका जुड़ाव है, उससे प्रेरणा मिलती है और इसलिए उसके नाम की मस्जिद बनानी है। यह भारत की एकता-अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अशुभ संकेत है।

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस बाबर को उसके मूल स्थान के कई इतिहासकार लुटेरा कहते हैं, अनेक भारतीय मुसलमान स्वयं को उससे जोड़ते हैं? हुमायूं कबीर के बाद तहरीक मुस्लिम शब्बन नामक संगठन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का एलान किया है। पता नहीं आगे कौन कहां बाबर के नाम पर और कुछ निर्माण की घोषणा कर दे। भारत विभाजन के पीछे बंगाल वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से कट्टरपंथियों के लिए बहुत बड़ी ताकत बना था। 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यहीं हुआ था, जिसमें कई सौ हिंदुओं को मारा गया था, ताकि गैर मुस्लिम डर जाएं और कांग्रेस दबाव में आए एवं ब्रिटिश सरकार के सामने मुसलमानों को अलग देश देने के अलावा चारा न बचे।

आखिर हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समुदाय के इतने लोगों के खड़े होने, रुपये देने का विश्लेषण कोई कैसे करेगा? कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख सकते हैं। अगर हुमायूं कबीर को बाबर के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद है तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी मानसिकता लंबे समय से सामने है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि "मुर्शिदाबाद में 70 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है। भाजपा के समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे।" आखिर मुर्शिदाबाद में भाजपा के समर्थक किस समुदाय के हैं? इसी वर्ष अप्रैल में मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के बहाने हुई हिंसा को याद करिए और हुमायूं कबीर के इस बयान को देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित तथ्य खोजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यहां की हिंसा पर दिल दहलाने वाले बातें कही थीं। उसमें कहा गया था कि हिंसा केवल हिंदुओं के विरुद्ध थी और सुनियोजित थी तथा स्थानीय तृणमूल के मुस्लिम नेता और पार्षद ने हिंसा का नेतृत्व किया। यह भी कि लोगों ने पुलिस से मदद मांगी, पर पुलिस ने न हिंसा रोकने की कोशिश की और न पीड़ितों को सुरक्षा देने की ही। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले बीएसएफ पर आरोप लगाया और फिर बाद में इसे भाजपा और संघ की साजिश करार देती रहीं।

पहले बंगाल के वामपंथी नेताओं और अब ममता ने ऐसे खतरनाक कट्टर हिंसक शेर की सवारी की है, जो उनके लिए भी संकट बन रहा है और देश के लिए भी। किसी भी समुदाय से उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इतिहास की कुछ बातें स्पष्ट हैं तो उन्हें स्वीकार कर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे। भारत में दृश्य इसके उलट हैं। यहां बाबर का खुलेआम गुणगान हो रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद देश को इस्लामी कट्टरवाद के कटु यथार्थ को समझना चाहिए और सरकार के साथ आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मुस्लिम समुदाय के अंदर भी ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार के व्यवहार को उचित नहीं मानते। उन्हें भी आगे आकर विरोध करना पड़ेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

खरमास के पहले बंट जाएगा मंत्रियों में जिलों का दायित्व

राज्य ब्यूरो, जागरण। पटना : नई सरकार की योजनाओं की जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक निगरानी के लिए खरमास (16 दिसंबर) शुरू होने से पहले मंत्रियों में जिलों का दायित्व बंट जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय को भाजपा की ओर से सूची की प्रतीक्षा है। संभावना है कि सूची मिलते ही वर्तमान 26 मंत्रियों के बीच जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी मंत्री का प्रभार सरकार बांट देगी। चर्चा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ ही वरिष्ठ एवं अनुभवी मंत्रियों के बीच दो-दो जिले का तत्काल दायित्व देने की पहल की जा रही है। अनुभवी मंत्री की बात करें तो नई सरकार में 17 पुराने मंत्री हैं, जबकि नौ नए हैं। वहीं, नई सरकार के गठन एवं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 38 जिलों को अब तक उनके प्रभारी मंत्री नहीं मिल सके हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित हो रही है। जिलों में विकास योजनाओं की मानीटरिंग, विभागीय समन्वय एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन लंबे इंतजार के कारण कई अहम निर्णय हिचकोले खा रहे हैं। जिलास्तर पर योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रभारी मंत्री की मौजूदगी बेहद जरूरी मानी जाती है।

नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक जिलों को नहीं मिल सके हैं उनके प्रभारी मंत्री

कई जिलों में बढ़ती जा रही लंबित परियोजनाओं की सूची

कई जिलों में लंबित परियोजनाओं की सूची बढ़ती जा रही है। विशेषकर शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क चौड़ीकरण, सिंचाई कार्यों और स्कूल भवन निर्माण जैसी योजनाएं प्रभारी मंत्री की स्वीकृति एवं निरीक्षण के अभाव में समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारी कई मुद्दों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि प्रभारी मंत्री के हस्तक्षेप के बिना बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा, आम जनता की शिकायतों एवं मांगों का निपटारा भी प्रभावित हुआ है। जिले में मंत्री के दौरे और जन सुनवाई कार्यक्रमों के अभाव में लोगों की अपेक्षाएं अधूरी रह जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही क्रय शक्ति

नाबार्ड की रिपोर्ट, 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने एक वर्ष पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदारी की

- उपभोग पर खर्च किया जा रहा मासिक आय का 67 प्रतिशत हिस्सा
- मासिक आय में सरकारी सब्सिडी का 10% तक योगदान

42.2 प्रतिशत परिवारों ने पिछले एक साल में आय बढ़ने की बात कही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी दरों में कटौती से सरकार ने पूरे देश में मांग में तेजी आने की उम्मीद जताई थी। इस बीच राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का ताजा अध्ययन बताता है कि जीएसटी दरों में कमी से पहले ही ग्रामीण भारत में मांग की रफ्तार तेज है। नाबार्ड की तरफ से गुरुवार को आठवें चरण के ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) के अनुसार, पिछले एक साल में ग्रामीण परिवारों की खर्च करने की क्षमता और इच्छा दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। नाबार्ड के मुताबिक, यह ग्रामीण परिवारों की वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि का सीधा प्रमाण है। ग्रामीण परिवारों की मासिक आय का दस प्रतिशत हिस्सा सरकारी सब्सिडी से मिला है।

सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक साल में अपनी खपत में वृद्धि की सूचना दी है। सर्वे शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खपत इस रफ्तार से कभी नहीं बढ़ी दिखी है। साथ ही, मासिक आय का 67.3 प्रतिशत हिस्सा अब खपत पर खर्च हो रहा है, जो सर्वे की शुरुआत से अब तक का सबसे ऊंचा अनुपात है। माना जा रहा है कि जीएसटी दरों की हालिया कटौती के बाद उपभोग की रफ्तार और ऊंचाई छू सकती है। इन परिवारों में भविष्य को लेकर भी आशावाद है। 42.2 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उनकी आय पिछले एक साल में बढ़ी है। हालांकि, 15.7 प्रतिशत ने आय में गिरावट की बात कही है लेकिन यह स्तर अभी का सबसे न्यूनतम स्तर है। अगले एक साल में आय बढ़ने की उम्मीद करने वालों का प्रतिशत 75.9 तक पहुंच गया, जो सितंबर 2024 से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

निवेश और औपचारिक कर्ज में भी रिकार्ड तेजी : सर्वे यह भी बताता है कि निवेश और औपचारिक कर्ज में भी रिकार्ड तेजी दर्ज की गई है जो बढ़ती आय के समानुपातिक माना जा सकता है। 29.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक साल में पूंजीगत निवेश (खेती और गैर-खेती दोनों क्षेत्रों में) बढ़ाया है। केवल औपचारिक स्रोतों (बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि) से कर्ज लेने वाले परिवारों का हिस्सा 58.3 प्रतिशत हो गया, जो सितंबर 2024 में 48.7 प्रतिशत था। ग्रामीण परिवारों की महंगाई धारणा घटकर 3.77 प्रतिशत रह गई है। यानी ये लोग समझ रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। सर्वे शुरू होने के बाद पहली बार यह स्तर चार प्रतिशत से नीचे आया है। 84.2 प्रतिशत परिवारों को लगता है कि महंगाई पांच प्रतिशत या उससे कम है। लगभग 90 प्रतिशत को उम्मीद है कि निकट भविष्य में भी यह पांच प्रतिशत से नीचे रहेगी। औसतन ग्रामीण परिवार की मासिक आय का 10 फीसद हिस्सा सब्सिडी वाले खाद्य, बिजली, पानी, रसोई गैस, उर्वरक, पेंशन, शिक्षा सहायता आदि के सरकारी हस्तांतरण से आ रहा है। कई परिवारों में यह हिस्सा 20 फीसदी से भी ज्यादा है। इसने भी मांग स्थिर बनाने में मदद की है।

> यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में मांग का पुनरुत्थान न तो मौसमी है और न ही किसी खास वर्ग तक सीमित। यह वास्तविक आय वृद्धि, कम महंगाई और मजबूत सरकारी समर्थन का संयुक्त परिणाम है। यह तस्वीर आने वाले दिनों में एफएमसीजी, दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, आवासीय निर्माण में जरूरी वस्तुओं आदि की मांग में तेजी का संकेतक है।
>
> **शाजी केवी,** चेयरमैन, नाबार्ड

कारोबार के लिए कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वर्ष 2025 में देश के क्रेडिट बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब लोग सिर्फ स्मार्टफोन या फ्रिज खरीदने के साथ कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार देने के लिए भी आत्मविश्वास के साथ कर्ज ले रहे हैं। उपभोक्ता वित्त कंपनी होम क्रेडिट इंडिया की गुरुवार को जारी वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट 'हाउ इंडिया बारोज' के मुताबिक, इस वर्ष सबसे ज्यादा 46 प्रतिशत लोगों ने स्मार्टफोन या घरेलू उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया है। पिछले वर्ष 48 प्रतिशत लोगों ने ऐसा किया था। कारोबार विस्तार के लिए 25 प्रतिशत लोगों ने कर्ज लिया, जो पिछले साल के 21 प्रतिशत से ज्यादा है। घर बनाने या उसकी मरम्मत करने वालों का हिस्सा 15 से घटकर 12 प्रतिशत हो गया है। वाहन खरीदने वालों की हिस्सेदारी छह से घटकर चार प्रतिशत हो गई है। शादी समारोह के लिए कर्ज लेने वालों का हिस्सा पिछले एक वर्ष में पांच से घटकर दो प्रतिशत पर आ गया है।

2047 तक जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का होगा 25 प्रतिशत योगदान

नई दिल्ली, प्रेट्र: वर्ष 2047 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का हिस्सा मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा और तब तक देश एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनने के लिए तैयार है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और जेड47 ने एक संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही है। डिजिटाइजिंग मेक इन इंडिया 3.0 रिपोर्ट में कहा गया है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम तेजी से घरेलू क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। रिपोर्ट में पांच क्षेत्रों - इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा, आटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा, और फार्मास्यूटिकल्स का उल्लेख किया गया है, जो 2047 तक 25 ट्रिलियन डालर के औद्योगिक अवसर का आधार बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार. आने वाले समय में भारत का मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र चार संभावित स्तंभों के चारों ओर घूम सकता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा, रणनीतिक गहराई को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से दक्षता को बढ़ाना शामिल है।

जब महिलाएं मजबूत होंगी तो आगे बढ़ेगा देश

हमारे हीरो कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तीकरण पर हुई चर्चा, वक्ताओं ने इंटरनेट मीडिया की चुनौती पर भी रखे विचार

पुस्तक मेला

जागरण संवाददाता, पटना : पटना पुस्तक मेले में गुरुवार को महिला सशक्तीकरण पर भी बातें हुईं। हमारे हीरो कार्यक्रम के दौरान डा. मोनी त्रिपाठी ने मंच संचालन करते हुए कहा कि महिलाएं मजबूत होंगी तभी देश सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा। समाज के विकास में आधी आबादी की भूमिका अहम है। इस बात को ध्यान में रखकर महिलाओं को आगे आना होगा। वे सशक्त होंगी तो आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल की अध्यक्ष नम्रता ने कहा कि महिलाएं अपने आप को मजबूत समझें। महिलाओं के सामने काफी चुनौतियां हैं पर उन्हें इसे पार करना होगा। उन्हें विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना होगा। अंकुरम रोश्रो की निदेशक डा. साधना झा ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने के लिए पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ानी होगी। पुलिस अधिकारी सीतू कुमारी ने कहा कि सरकार के आरक्षण का फायदा महिलाओं को मिल रहा है। इसके जरिए कई महिलाएं सरकारी नौकरी पाने के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं।

चुनौती के रूप में आया है इंटरनेट मीडिया: प्रिंट पत्रकारिता की चुनौतियां और सरोकार पर पत्रकार गिरिधर झा ने कहा कि आज के दौर में इंटरनेट मीडिया सबसे बड़ी चुनौती है। आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस (एआइ) नए पत्रकारों का प्रभावित कर रही है। उनकी शब्दावली को खा रही है। पाठक वर्ग का सिमटना अखबारों और पत्रिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर विचार करना होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक कुमार वरुण ने किया। सिनेमा उनेमा सत्र बिहार के सिनेमा पर मनोज पांडेय ने कहा कि फिल्म के जरिए बिहार की छवि को बेहतर बनाने की जरूरत है। प्रदेश की मासूमियत सिनेमा में आना बाकी है। फिल्म निर्देशक रंजन कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की मिट्टी से जुड़ी बातों को धारावाहिक में रखता हूं। इससे प्रस्तुति जीवंत हो जाती है और दर्शक इसका पूरा आनंद लेते हैं। इस दौरान राजीव रंजन को सम्मानित किया गया। पाठकों ने संजय मिश्रा अभिनीत फिल्म अधीन का आनंद उठाया।

मुख्य मंच पर कार्यक्रम हमारे हीरो में चर्चा करती बाएं से डा. मोनी त्रिपाठी, डा.साधना झा, नम्रता नाथ व सीतू कुमारी ● जागरण

विहार की लोक संस्कृति की पुस्तकें पाठकों की पसंद

पटना : पटना पुस्तक मेला कल, साहित्य, शिक्षा, संगीत और किस्सागोई से भरा विविधताओं वाला दिन रहा। गुरुवार को मेले में पाठकों ने बिहार के संदर्भ में कला, संस्कृति, धरोहर, पर्यटन, खान-पान को लेकर पुस्तकों की मांग रही। मेले में स्टाल लगाए प्रभात प्रकाशन के अमित कुमार ने बताया कि यहां पर पर पाठक बिहार के पर्यटन स्थल, बिहार के मेले, बिहार के गुरुद्वारे, पर्व त्योहार से जुड़ी पुस्तकों की खरीदारी कर रहे हैं। लेखक सुबोध नंदन की पुस्तक इन दिनों चर्चा में है। इसके अलावा युवा स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम की पुस्तक अग्नि की उड़ान को पसंद कर रहे हैं।

यात्रा कर समझी जा सकती है बिहार की विशिष्ट संस्कृति

बिहार को समझने के लिए पुस्तकों के बजाया यात्रा जरूरी है। लेखक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की यात्रा कर लोग इसकी लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। बिहार के खानपान पर रविशंकर उपाध्याय ने कहा कि स्थानीय व्यंजनों को प्रसारित करने की जरूरत है। मौसम के अनुरूप प्रदेश का खानपान बदलता रहता है। धर्म और जीवन सत्र के दौरान सफदर इमाम काजमी ने कहा कि हर धर्म मानवता का संदेश देती है। स्वास्थ्य परिचर्चा के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सुनील ने कहा कि मोबाइल, लैपटाप का अधिक प्रयोग से आखों की रोशनी कम हो रही है।

स्वास्थ्य परिचर्चा में भाग लेते डा. विकास शेकर, डा. शशि मोहनका, डा. सुनील कुमार सिंह, डा. प्रीति शर्मा, डा. प्रतीक आनन्द, डा. रंजना कुमार व अन्य ● जागरण

बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति को मिली जमकर सराहना

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को आनंदित किया। डा. मोनी त्रिपाठी एवं सरिता मिश्रा के संयोजन में स्कूल उत्सव कार्यक्रम के तहत दून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मोबाइल के दुष्प्रभाव पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। बच्चों ने प्रदेश के पारंपरिक गीत सोहर पेश कर तालियां बटोरी। बच्चों को चंद्राभा फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पटना पुस्तक मेला में आयोजित स्कूल उत्सव कार्यक्रम में दून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने "मोबाइल एडिक्शन" विषय पर नृत्य प्रस्तुत किया ● जागरण

बिहार ने ड्रा कराया मैच, हरियाणा को मिला अधिक अंक

जागरण संवाददाता, पटना: कूच बिहार ट्राफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में गुरुवार को हरियाणा के एक पारी में बनाए 541 रनों के विशाल स्कोर के सामने बिहार ने मैच ड्रा करा लिया। मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार टीम पहली पारी में 430 रनों पर सिमट गई। ऐसे में मेहमान टीम को 111 रनों की बढ़त मिल गई। लीड लेने के कारण हरियाणा को मुकाबले में तीन और बिहार को एक अंक मिले।

अंडर-19 मैच में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोक्ष मुदगिल के दोहरे शतक की मदद से 145.4 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 541 रनों पर पारी घोषित कर दी। मोक्ष ने 370 गेंद पर 29 चौके और एक छक्के की सहायता से 221 रनों की पारी खेली। तनमय बलोदा ने 66, निधहीश गौर ने 63, सुम्मी कदीबन ने 58, कप्तान रुद्राश नरवाल ने 55 रन बनाए। बिहार की तरफ से योगेश्वर कुमार ने तीन और मोहित कुमार, सत्यम कुमार एवं आर्यन पटेल ने क्रमशः दो-दो विकेट लिए।

आयुष और आलम ने जड़ा शतक: हरियाणा की बड़ी पारी के जवाब में बिहार के सलामी बल्लेबाज आयुष रविशंकर ने शतक जड़कर ठोस शुरुआत की। मो. आलम के 102 और सार्थक झा के अभिजित 80 रनों की बदौलत बिहार ने मुकाबले के अंतिम दिन 159.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 430 रन बनाए। दूसरी पारी में हरियाणा की टीम ने मैच खत्म होने तक 17.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। विकेट कीपर बल्लेबाज यश 44 रन पर अभिजित रहे। निधहीश गौर 31 और गिरीश दहिया 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बिहार की ओर से मोहित कुमार और योगेश्वर कुमार को एक-एक सफलता मिली।

मुकाबला

- मोइनुल हक स्टेडियम में हरियाणा के 541 रनों के जवाब में बिहार की टीम 159.3 ओवर में 430 रनों पर सिमटी
- मेहमान टीम के मोक्ष मुदगिल ने खेली 221 रनों की पारी, बिहार के आयुष और आलम ने मुकाबले में जड़ा शतक

मोइनुलहक स्टेडियम में कूच बिहार ट्राफी टूर्नमेंट में मैच खेलते खिलाड़ी ● जागरण

नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग से आए लोग साथ लाए हैं अपनी लोक संस्कृति भी

राज्य में पहली बार आयोजित हुआ हिमालयन आरेंज टूरिज्म फेस्टिवल, लोगों को मिली जानकारी

जागरण संवाददाता, पटना : शहर के सिटी माल में एसोसिएशन फार कंजर्वेशन एंड टूरिज्म की ओर से सातवें हिमालयन औरेंज टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन राज्य में पहली बार हो रहा है। इसके जरिए दूसरे देशों की लोक संस्कृति और सभ्यता से परिचित होने के साथ देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के साथ भारत का पुराना संबंध रहा है। यहां पर आए किसान, कलाकार, उद्यमी अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के साथ खान-पान के बारे अवगत करा रहे हैं। आइएएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि हिमालय के तराई वाले इलाके नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि जगहों से आए लोग अपने साथ अपनी लोक संस्कृति लाए हैं। भले ही हम सभी भौगोलिक रूप से दूर है पर संस्कृति से जुड़े हैं। ऐसे कार्यक्रम आपसी प्रेम को मजबूती प्रदान करेंगे। आज के समय में ग्रामीण पर्यटकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। एसोसिएशन की ओर से भारत और नेपाल के सांस्कृतिक व पर्यटन को लेकर एमओयू (समझौता) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

हिमालयन आरेंज टूरिज्म फेस्टिवल का उद्घाटन करते पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, आइपीएस विकास वैभव व अन्य • जागरण

- सिक्किम के पूर्व राज्यपाल ने कहा- ऐसे उत्सव से देशों के बीच प्रगाढ़ होंगे रिश्ते, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
- ऐसे कार्यक्रम आपसी प्रेम को मजबूती प्रदान करेंगे, आज के समय में ग्रामीण पर्यटकों को बढ़ावा देने की है जरूरत

यह उत्सव बिहार के किसानों के लिए अनमोल : रामकृपाल

कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि यह उत्सव बिहार के किसानों के लिए अनमोल अवसर लेकर आया है। संतरा उत्पादन की उन्नत तकनीक सीखकर हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। ऐसे आयोजनों से न केवल कृषि एवं बागवानी को नई दिशा मिलती है, बल्कि कृषि पर्यटन के नए आयाम भी विकसित होंगे। किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जीता दिल

समारोह को यादगार बनाने को लेकर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीता। ओडिशी नृत्यांगना डा. पांपी पाल ने अपनी प्रस्तुति के जरिए भगवान जगन्नाथ के अलग-अलग रूपों के साथ गणेश का वंदन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद ब्लू बिल्स विद्यालय के बच्चों ने कजरी गीत कैसे खेलय सावन में कजरिया ननदी.. से तालियां बटोरी। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने को लेकर नेपाल से आए कलाकारों ने लोकनृत्य का दमदार प्रदर्शन सभी को मोहित किया। मंच का संचालन आरजे विजेता ने किया। विभिन्न जगहों से आए लोगों ने स्टाल पर अपने खाद्य पदार्थ, कलाओं को प्रदर्शित कर ध्यान आकर्षित किए। मौके पर टूरिज्म एसोसिएशन आफ बिहार के अध्यक्ष एसके सिंह, समन्वयक गितांली लाहिड़ी, म्हाश्वेता राय, तनिष्ठा रक्षित, अमरेंद्र पांडेय, रामलाल खेतान आदि मौजूद रहे।

सिटी सेंटर माल में आयोजित हिमालयन आरेंज टूरि

पटना में बनाया जाएगा देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : पटना में देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार व बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को इस संबंध में बैठक हुई। इसमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन व एजेंसी चयन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, मनोज कुमार सिंह एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल)) के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की उपस्थिति में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने परियोजना पर विस्तृत पर प्रेजेंटेशन दी। बिहार म्यूजियम में आयोजित बैठक में महानिदेशक द्वारा ऊर्जा संग्रहालय परियोजना की अवधि, एजेंसी की योग्यता एवं चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

राजधानी स्थित करबिगहिया के बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की करीब तीन एकड़ भूमि को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा। उल्लेखनीय है कि यह देश का पहला और दुनिया का चौथा समर्पित ऊर्जा संग्रहालय होगा, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना है। बैठक में बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता (सिविल), कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार एवं परियोजना के लिए गठित विशेष कमिटी के सदस्य चंद्रशेखर कुमार, विनय कुमार, सौम्या, नुपूर व सुश्री केका कुमारी उपस्थित थीं।

संग्रहालय का भ्रमण करते उद्योगपति अजय पीरामल ● सौ : संग्रहालय

बिहार संग्रहालय सबसे उत्कृष्ट और शानदार

जासं, पटना : उद्योगपति व पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल ने गुरुवार को बिहार संग्रहालय का भ्रमण कर कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद प्रशंसा की। संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत करने के बाद ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराया। उन्होंने बिहार संग्रहालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि संग्रहालय सबसे उत्कृष्ट और शानदार है। लोगों को संग्रहालय का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। इससे अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है।

पर्यटकों को भा रहा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व स्मृति स्तूप

जागरण संवाददाता, पटना : वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संग्रहालय का तीन लाख 57 हजार से अधिक पर्यटकों ने भ्रमण किया है। इसमें म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, अल्जीरिया, मलेशिया, कोरिया, थाइलैंड, अल्बानिया, नेपाल, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों से पर्यटकों ने भव्य स्तूप का दर्शन किया। स्तूप के दर्शन को लेकर आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। 29 जुलाई को स्मृत का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। 72 एकड़ के भूखंड पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि स्तूप की भव्यता पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। संग्रहालय परिसर को अंदर से सुंदर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संग्रहालय परिसर में सिंबल, तारा मुद्रा, लिच्छवि से जुड़ी प्रतिकृति को प्रतिष्ठित किया गया है। संग्रहालय में प्रदर्श कार्य तेजी से प्रगति पर है।

संग्रहालय का तीन लाख 57 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया भ्रमण, पर्यटकों ने देखा भव्य स्तूप

टी-20 में भारतीय टीम की दूसरी सबसे बड़ी हार

दूसरे टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हराया डिकाक ने खेली 90 रन की पारी

रवि अटवाल • जागरण

चंडीगढ़: पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रनों से हराकर सीरीज में शानदार वापसी कर ली। इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में यह दूसरी सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने भारत को वेलिंग्टन के मैदान में 80 रनों से हराया था।

मुल्लांपुर(न्यू चंडीगढ़) के मैदान में पहली बार हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 213 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई। भारतीय पारी में अकेले तिलक वर्मा डटे रहे और उन्होंने आखिर तक बल्लेबाजी की। उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। तिलक ने 34 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने दो चौके और पांच छक्के लगाए।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया। उनकी ओर से ओटनिल बार्टमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने महज 24 रन देकर चार विकेट झटके। एनगिडी, जेनसेन और सिपामला को दो-दो विकेट मिले।

21 पारियों से अर्धशतक नहीं जड़ सके सूर्य: टी-20 विश्व कप से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की खराब फार्म भी टीम के लिए चिंता बनी हुई है। वीरवार को भी सूर्य का बल्ला नहीं चला और वह महज पांच रन बनाकर चलते बने। पिछली 21 पारियों से वह अर्धशतक नहीं बना सके हैं। इन 21 पारियों में वह केवल चार बार ही 20 से ज्यादा रन बना सके हैं।

संन्यास से लौटे डिकाक का तूफान: संन्यास के बाद मैदान पर लौटे क्विंटन डिकाक ने भारत के विरुद्ध तूफानी पारी खेली। हालांकि वह शतक से चूक गए। डिकाक ने महज 46 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली। जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने विशाल स्कोर खड़ा। डिकाक ने अपनी पारी में सात छक्के जड़े। आखिरी ओवरों में डोनोवेन फरेरा और डेविड मिलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। फरेरा ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जबकि मिलर ने 12 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। दोनों ने महज 23 गेंदों में 53 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी की। इसके बाद डी काक ने कप्तान एडन मार्करैम के साथ दूसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की। डिकाक ने ब्रेविस के साथ भी 19 गेंदों में 35 रन जोड़े। डिकाक 90 के स्कोर पर अक्षर पटेल के ओवर में रन आउट हो गए। उनका करियर का यह 17वां अर्धशतक था। उनके बाद फेरेरा और मिलर ने टीम के लिए उपयोगी पारियां खेली।

टास जीतकर गेंदबाजी करना पड़ा भारी: इससे पहले भारत ने टास जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने पिछले 10 टी-20 मुकाबलों में तीसरी बार टास जीता। भारत दूसरी पारी में ओस का फायदा लेना चाहता था, लेकिन हुआ इसके उलट। भारतीय पारी लगातार लड़खड़ाती रही। टीम ने शुरुआत में ही महज 32 रन पर ही तीन केट गवां दिए थे।

वरुण रहे सबसे सफल गेंदबाज: वरुण चक्रवर्ती सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने चार ओवरों में 29 रन देकर दो विकेट लिए। उनके अलावा एक विकेट अक्षर पटेल को मिला। बाकी कोई गेंदबाज असरदार नहीं दिखा। जसप्रीत बुमराह भी विकेट हासिल नहीं कर सके और उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 11.20 की इकोनामी से 45 रन दिए।

अर्शदीप ने 13 गेंद का ओवर डालकर नवीन उल हक की बराबरी की

युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक न चाहने वाला रिकार्ड अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 11वें ओवर में उन्होंने 18 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने सात वाइड गेंद फेंकी। उन्होंने कुल 13 गेंद का ओवर फेंका। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे लंबा ओवर फेंकने के रिकार्ड की बराबरी कर ली। उनसे पहले अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने भी पिछले साल हरारे में जिंबाब्वे के विरुद्ध 13 गेंदों का ओवर फेंका था। अपने घर में उनका दिन कुछ खास नहीं रहा और मुकाबले में वह सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 54 रन दिए और उन्हें मुकाबले में कोई विकेट भी नहीं मिला।

भारत की टी-20 में सबसे बड़ी हार

रन	बनाम	साल
80	न्यूजीलैंड	2019
51	द.अफ्रीका	2025
49	आस्ट्रेलिया	2010
49	द.अफ्रीका	2022
47	न्यूजीलैंड	2016

54 रन अर्शदीप ने अपने करियर में चार ओवर में दूसरे सर्वाधिक लुटाए, इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ही 2022 में गुवाहाटी में 62 रन दे चुके हैं

द.अफ्रीका के विरुद्ध सर्वाधिक छक्के (भारतीय)

खिलाड़ी	छक्के
तिलक वर्मा	27
सूर्यकुमार यादव	26
संजू सैमसन	19
रोहित शर्मा	16

भारत के विरुद्ध द. अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

स्कोर	स्थान	साल
227/3	इंदौर	2022
221/3	गुवाहाटी	2022
219/4	जोहानिसबर्ग	2012
213/4	मुल्लांपुर	2025

शाट लगाते हुए क्विंटन डिकाक • आइएएनएस

युवराज-हरमनप्रीत के नाम पर स्टैंड

मैच शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज सितारों युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। स्टेडियम के दो स्टैंड आधिकारिक रूप से इनके नाम पर समर्पित किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी मौजूद थीं। स्टैंड का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से घोषित 11-11 लाख रुपये की राशि हरमनप्रीत, हरलीन और अमनजोत को भेंट की। इनके अलावा महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच मुनीष बाली को भी पांच लाख रुपये दिए गए।

युवराज और भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत • संजय धिड़ियाल

स्कोर बोर्ड

टास: भारत (गेंदबाजी) प्लेयर आफ द मैच: क्विंटन डिकाक

दक्षिण अफ्रीका: 213/4 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
डिकाक रन आउट	90	46	5/7
हेंड्रिक्स बो. वरुण	8	10	0/1
मार्करैम का. अक्षर बो. वरुण	29	26	1/2
ब्रेविस का. तिलक बो. अक्षर	14	10	1/1
फरेरा अविजित	30	16	1/3
मिलर अविजित	20	12	2/1

अतिरिक्त: 22. विकेटपतन: 1-38 (हेंड्रिक्स, 4.1), 2-121 (मार्करैम, 11.6), 3-156 (डिकाक, 15.1), 4-160 (ब्रेविस, 16.1). गेंदबाजी: अर्शदीप 4-0-54-0, बुमराह 4-0-45-0, वरुण 4-0-29-2, अक्षर 3-0-27-1, हार्दिक 3-0-34-0, शिवम 2-0-18-0

भारत: 162 (19.1 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
अभिषेक का. डिकाक बो. जेनसेन	17	8	0/2
शुभमन का. हेंड्रिक्स बो. नगिडी	0	1	0/0
अक्षर का. हेंड्रिक्स बो. बार्टमैन	21	21	1/1
सूर्यकुमार का. डिकाक बो. जेनसेन	5	4	1/0
तिलक का. मार्करैम बो. नगिडी	62	34	2/5
हार्दिक का. ब्रेविस बो. सिपामला	20	23	0/1
जितेश का. बार्टमैन बो. सिपामला	27	17	2/2
शिवम बो. बार्टमैन	1	2	0/0
अर्शदीप का. मिलर बो. बार्टमैन	4	3	1/0
वरुण का. मार्करैम बो. बार्टमैन	0	2	0/0
बुमराह अविजित	0	0	0/0

अतिरिक्त: 5 (बा: 3, लेबा: 1, वा: 1), विकेटपतन: 1-9 (शुभमन, 0.5), 2-19 (अभिषेक, 1.6), 3-32 (सूर्यकुमार, 3.5), 4-67 (अक्षर, 7.3), 5-118 (हार्दिक, 14.2), 6-157 (जितेश, 17.5), 7-158 (शिवम, 18.1), 8-162 (अर्शदीप, 18.4), 9-162 (वरुण, 18.6). गेंदबाजी: नगिडी 3.1-0-26-2, जेनसेन 4-0-25-2, सिपामला 4-0-46-2, फरेरा 1-0-14-0, बार्टमैन 4-0-24-4, लिंडे 3-0-23-0